



बौद्धों की एक परम्परा तिब्बत के पठार की नदियों में रहने वाले ऊदबिलावों (आर्ट्स) के लिए वरदान बन गई है। "इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इन्टर रिलिजस एंड इन्टरकल्चरक स्टडीज" में प्रकाशित 2020 के एक शोध में बताया गया है कि, बौद्धों की एक धार्मिक परंपरा है "फैंगशौंग" (मुक्ति), इसमें बाजार में बिकने के लिए आए जानवरों को खरीदकर उन्हें जीवनदान दिया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ कहते हैं कि, यह रस्म "ऋण चुकाने", "दुर्भाग्य और खराब स्वास्थ्य को खत्म करने" तथा "किसी जीव के जीवन को बहाने" का एक जरिया है। प्रथा के अनुरूप, दक्षिण-पश्चिमी चीन में तिब्बत के पठार पर रहने वाले बौद्ध धर्मावलंबी बाजार से मछलियाँ खरीदकर, उन्हें स्थानीय नदियों में छोड़ देते हैं। "करंट जूलॉजी" जर्नल में छपे शोध के अनुसार, ये मछलियाँ नदियों में रहने वाले आर्ट्स का भोजन बन गई हैं। इतना ही नहीं, प्रायः कूशियन कार्प तथा कॉमन कार्प जैसी बाहरी मछलियों को बाजार से खरीदकर नदियों में छोड़ा जाता है। इन बाहरी मछलियों से बीमारी फैलने का डर होता है, इसके अलावा स्थानीय मछलियों को इन बाहरी मछलियों के साथ भोजन के अपने संसाधन को साझा करना पड़ता है। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने बाहरी मछलियों नदियों में छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन फिर भी हर साल हजारों मछलियाँ नदियों में छोड़ी जाती हैं। परंतु, शोधकर्ताओं ने देखा कि, इसके बावजूद भी स्थानीय नदियों में इन मछलियों की तादाद ज्यादा नहीं है। वर्ष 2022 में लिए गए सैम्पल में मात्र दो कूशियन कार्प मिलीं। असल में बात यह है कि, यूरोशियन आर्ट्स इन मछलियों को बहुत पसंद करते हैं। यह जानने के लिए कि, धार्मिक रस्म के तहत नदियों में छोड़ी गई इन बाहरी मछलियों को आर्ट्स खा रहे हैं या नहीं, टीम ने आर्ट के मल के नमूने लिए और पाया कि, हालांकि नदी में बाहरी प्रजाति की मछलियों की संख्या स्थानीय मछलियों की तुलना में कम है, लेकिन इसके बावजूद भी आर्ट्स के मल में बाहरी प्रजाति की मछलियों की उपस्थिति अधिक पाई गई। शोधकर्ताओं का कहना है कि, इस प्रकार आर्ट्स नदी के इको सिस्टम में बाहरी मछलियों की आबादी को नियंत्रित रख रहे हैं।

चीन के रक्षा मंत्री शांग फू भी अचानक गायब हुए

इससे पहले चीन के विदेश मंत्री किन गांग भी अचानक लापता हो गए थे

-अंजन राय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। चीन सरकार के विभागों में बार-बार हो रहे बदलाव नेतृत्व में अनिश्चय की स्थिति के सूचक हैं। चीन के विदेश मंत्री किन गांग के एकाएक गायब हो जाने के बाद, चीन सरकार के एक और शीर्ष सदस्य अचानक अदृश्य हो गये हैं। ली शांग फू, जो अभी हाल तक चीन के रक्षा मंत्री थे, उस समय के बाद दिखाई नहीं दे रहे, जब उन्होंने एक वियतनाम प्रतिनिधिमंडल के साथ हो रही उच्चस्तरीय मीटिंग के एक राउंड से स्वयं को एकाएक हटा लिया था। उन्होंने यह कदम दोनों देशों के बीच सीमा संबंधी एक बिन्दु पर चर्चा के समय उठाया था। जनरल ली इससे पूर्व चीनी रक्षा खरीद के कार्य से जुड़े रहे हैं। इससे पूर्व भी, चीन के शीर्ष नेतृत्व ने देश की न्यूक्लियर फोर्स तथा मिसाइल विभाग के शीर्ष सदस्यों को पूरी तरह बर्खास्त कर दिया था। चीन की न्यूक्लियर फोर्स तथा मिसाइल विभाग

- महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों का इस तरह लापता हो जाना चीन के नेतृत्व पर कई सवाल खड़े करता है।
- वियतनाम डेलीगेशन से अचानक हटने के बाद से ली शांग फू कहीं भी नजर नहीं आए हैं।
- इससे पहले चीन की न्यूक्लियर फोर्स और मिसाइल कार्यक्रम को देख रहे एक टॉप अधिकारी को भी हटा दिया गया था।
- इन घटनाओं को चीन में सरकार के उच्चतम स्तर पर व्याप्त असुरक्षा और संदेह का संकेत माना जा रहा है।

से जुड़े बहुत से मुख्य अधिकारियों को एकाएक हटा दिया गया था। चीनी सरकार तंत्र के मुख्य क्षेत्रों में हुये ये तीन बदलाव सरकार के शीर्ष स्तर पर खलबली के संकेत दे रहे हैं। सरकार के इन उच्च स्तरों पर चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह अपारदर्शिता है। यह चीन सरकार के उच्चतम स्तरों पर असुरक्षा एवं संदेह के स्तर का संकेत भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इस समय चीनी सरकार की स्थिति को इन प्रमुख क्षेत्रों में विद्रोह का डर

लगातार सता रहा हो तथा उन्हें स्वयं को हटा दिये जाने का खतरा दिखाई दे रहा हो। विशेषज्ञों की सोच है कि एकाएक हो रहे ये बदलाव चीन सरकार अशांति के व्यापक स्तर के संकेत हैं। जापान में अमेरिकन राजदूत, जो चीन तथा चीन संबंधी मामलों पर पैनी नजर रखने के लिये जाने जाते हैं, ने एक्स, पूर्ववर्ती ट्विटर, पर अपने आकडन्त में कटाक्ष करते हुये लिखा था कि इस समय चीनी सरकार की स्थिति बहुत कुछ अगाथा क्रिस्टी की जासूसी

कहानी "एंड वैन देयर वर नन"। राजदूत इमैनुअल रैम ने एक्स में लिखा, "राष्ट्रपति शी के मंत्रिमंडल का लाइनअप इस समय अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास "एंड दैन दे पर वर नन" से मिलता-जुलता लग रहा है। पहले, विदेश मंत्री किन गैंग अदृश्य हुये, उसके बाद "रॉकेट फोर्स" के कमांडर गायब हुये और अब रक्षा मंत्री ली शांगफू दो सप्ताह से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने चीन के इस गोरख धंधे को "मिस्ट्री इन चाइना" की संज्ञा दी। अचानक गायब हो जाना और अचानक सामने आ जाने का यह तरीका चीन के बैटफ्रेंड रूस जैसा है। यूक्रेन वॉर के दौरान रूस की सेना के कई जनरल लुप्त हैं। चीन के केस में शी कैबिनेट के इन दोनों मंत्रियों को अभी भी स्टेटे काउन्सिलर्स के रूप में संबोधित किया जा रहा है अर्थात् वे अभी भी कैबिनेट के सदस्य हैं। चीन के रक्षा मंत्रालय के रक्षा मंत्री ली का काफी भारी समर्थन है (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बघेल से अलग राह चलने के फेर में अपनी ही पार्टी को शर्मिंदा कर दिया सिंह देव ने

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल और उपमुख्यमंत्री की आपसी रार, नए आयामों पर पहुंची

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। संघीय व्यवस्था के मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव एकमत नहीं हैं। रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

- छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 23 अगस्त को पत्र लिखकर प्र.मंत्री मोदी से राज्य के बकाया 6000 करोड़ रु. देने को कहा था तथा आरोप लगाया था कि, मोदी ई.डी. के जरिए उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं।
- वहीं प्र.मंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव ने उनकी जम कर प्रशंसा की और कहा कि, केन्द्र सरकार से हमने जो मांगा वह मिला है, केन्द्र ने कभी भी पक्षपात नहीं किया।
- सिंह देव असल में बघेल से नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि, बघेल ने उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं अवरुद्ध की हैं।
- हालांकि, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समझौता करवा दिया था, पर, लगता है इस समझौते का अपेक्षित परिणाम नहीं निकला।

के साथ मंच साझा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा, "केन्द्र सरकार राज्य के खिलाफ पूर्वाग्रह नहीं रखती। मैंने

कभी पूर्वाग्रह का अनुभव नहीं किया। राज्य सरकार के रूप में हमने केन्द्र से जो भी मांगा उसने सहयोग किया। मुझे विश्वास है कि आपसी सहयोग से हम देश और राज्य को आगे ले जाएंगे।" सिंहदेव की स्थिति मुख्यमंत्री बघेल से अलग दिख रही है। जिन्होंने गत माह केन्द्र सरकार पर राज्य की बकाया राशि जारी न करने का आरोप लगाया था। 23 अगस्त को बघेल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर विकेन्द्रीकृत चावल योजना के बकाया 6000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की थी। बघेल मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि वह उन्हें डराने तथा राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए ई.डी. और आयकर जैसी जांच एजेंसियों का दुराप्रहर्षण उपयोग कर रही है। बताया जाता है कि सिंहदेव बघेल से अलग राह ही चलते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के ढाई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'पत्रकारों का बायकाँट सेंसर शिप'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। भारतीय जनता पार्टी ने "धर्मण्डिया" गठजोड़ - इण्डिया ब्लॉक -के घटकों द्वारा कुछ पत्रकारों को बायकाँट करने और उन्हें दो धमकी की कड़े शब्दों में निंदा की है। भाजपा ने कहा, ऐसा अतिनिन्दनीय

- भाजपा ने विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा कुछ टी.वी. एंकरों के विचारों पर यह भी कहा कि "धर्मण्डिया" गठबंधन के नेताओं की पत्रकारों के बारे में बेवद घटिया सोच है और उनकी मानसिकता प्रेस का दमन करने की है।

निर्णय लेकर, "धर्मण्डिया" गठजोड़ ने एक बार और अपनी अत्यधिक दमनकारी, तानाशाही और सेंसरशिप वापस लाने की नकारात्मक सोच को उजागर किया है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के गठजोड़ द्वारा उठाए गए (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कांग्रेस पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतेगी'

हैदराबाद में आज शुरु हुई सी.डब्ल्यू.सी. की दो दिवसीय बैठक में वेणुगोपाल ने दावा किया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। हैदराबाद में होने वाली सी.डब्ल्यू.सी. की द्विदिवसीय मीटिंग से पहले, कांग्रेस महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने विश्वास जताया है कि पार्टी इस वर्ष पाँच राज्यों, जिनमें तेलंगाना भी शामिल है, के आसन्न विधानसभा चुनावों में विजय प्राप्त करेगी।

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया कि सी.डब्ल्यू.सी. के गठन के बाद, उसकी पहली मीटिंग शनिवार एवं रविवार को हैदराबाद में होगी। उन्होंने कहा कि सी.डब्ल्यू.सी. विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करेगी। विपक्षी गठबंधन मीडिया द्वारा 14 टी.वी. एंकरों को ब्लैकलिस्ट कर दिये जाने को लेकर पूछे गये एक सवाल के उत्तर में, वेणुगोपाल ने कहा, "हमें पूरी-पूरी आशा है कि (लोकतंत्र का) चौथा

- बैठक से पूर्व कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने पत्रकारों से वार्ता की और कहा कि, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी.आर. और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, के.सी.आर. से हमारा कोई सरोकार नहीं है।

स्वप्न, मीडिया लोकतंत्र का संरक्षक एवं उद्धारक बनेगा, जैसा कि पहले हुआ करता था।" उन्होंने कहा, मीडिया की भूमिका यह होती है कि जब-जब सरकार कोई गलती करे, तो वह सरकार को सही रास्ते पर लाये। मीडिया का कर्तव्य है कि वह सरकार को सुधारे तथा इसी प्रकार मीडिया वह विपक्ष की आवाज का सहयोग किया करता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मीडियाकर्मी केवल एक ही काम कर रहे हैं- सरकार का समर्थन करना तथा विपक्ष को बुरी तरह ध्वस्त करना। यह पत्रकारिता नहीं है। हम ऐसा नहीं मान रहे कि यह पत्रकारिता है, यह साफ तौर पर मोदी

सरकार के पक्ष में एक "स्पॉन्सर्ड जर्नलिज्म" है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया है कि उसका कोई घटक दल इन एंकरों वाले किसी कार्यक्रम में नहीं जायेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव द्वारा प्रधानमंत्री को इस बात के पत्र लिखे जाने पर कि सोमवार से शुरु हो रहे संसद के पंचदिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया जाये, वेणुगोपाल ने कहा कि यह विधेयक कांग्रेस का शिष्ट है। उन्होंने कहा, "हमने यह विधेयक एक सदन (राज्यसभा) में पारित कर दिया था किन्तु दूसरे सदन में यह पहले दिन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी को अंतरिम राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। भारत राष्ट्र समिति की एम.एल.सी. और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव की पुत्री कविता को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को

- के. कविता, जो तेलंगाना की सत्तारूढ़ पार्टी की एम.एल.सी. हैं, को दिल्ली की आबकारी नीति की अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितम्बर तक राहत दी है।

दिल्ली की आबकारी नीति की अनियमितताओं के मामले में 26 सितम्बर तक के लिए अंतरिम राहत प्रदान की। ई.डी., जिसने उन्हें शुक्रवार को सम्मन दिया था ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कविता को 26 सितम्बर तक उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जाएगा।

भाजपा नेताओं के भाषणों व बयानों से "हिन्दुत्व" लुप्त हुआ, अब "सनातन" पर ज्यादा फोकस

आम चुनावों तक भाजपा नेता इंडिया गठबंधन को सनातन धर्म का शत्रु बताते रहेंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सत्तारूढ़ भाजपा ने नवगठित इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के आगामी चुनाव में वषों से चल रहे अपने हिन्दुत्व एजेंडा की बजाय इस बार सनातन धर्म काम में लेना चाहती है। सूर्यो के अनुसार, जमीनी स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये मौखिक निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने वक्तव्यों और संवाद में हिन्दुत्व के बजाय सनातन शब्द का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वे "धर्मण्डिया गठबंधन" के कुटिल इरादों को हराएं और एकजुट रहें। पार्टी की

- शुक्रवार को एन.डी.टी.टी. पर एक साक्षात्कार में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयनिधि स्टालिन के सनातन संबंधी बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया, खासकर कांग्रेस व सोनिया गांधी पर तीखा प्रहार किया और कहा कि, यह सनातन धर्म का विरोध नहीं, बल्कि सनातन धर्म को नष्ट करने की चाल है।
- भाजपा ने रणनीति में यह परिवर्तन इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है कि, हिन्दुत्व की बजाय सनातन व हिंदू शब्द ज्यादा स्वीकार्य है।
- ज्ञातव्य है कि, आर.एस.एस. हमेशा से हिन्दुत्व पर जोर देती रही है, क्योंकि उसकी सोच है कि, सनातन कमजोरों का धर्म है।

सीतारमण ने कहा कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के समर्थक भारत को तोड़ना चाहते हैं। भाजपा के सहयोगियों ने भी कांग्रेस, विशेषकर सोनिया गांधी निशाना बनाया। हालांकि कांग्रेस ने खुद को द्रमुक नेता के बयान से दूर कर लिया था। मंत्री ने खुलेआम कहा कि यह सनातन धर्म का विरोध नहीं है बल्कि उसको मिटाने की चाल है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी घटक ने इस बयान की निंदा नहीं की। एन.डी.टी.टी. से बात करते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि सनातन का विरोध द्रमुक की घोषित नीति है और वे इसकी गवाह हैं। सीतारमण ने कहा, "तमिलनाडु

के लोगों ने कष्ट भोगा। शेष देश भाषा की समस्या के कारण इसको समझ नहीं पाया। हमेशा से यही होता रहा है। अब सोशल मीडिया के कारण मंत्री ने क्या कहा इसे समझने के लिए किसी अनुवादक की जरूरत नहीं है। यह आश्चर्यजनक नहीं है। द्रमुक के नेता पिछले 70 साल से यही कर रहे हैं। यह दोगलापन है।" उदयनिधि स्टालिन के बयान को संविधान का मखौल बताते हुए निर्मला ने आरोप लगाया कि वे जानबूझ कर विवादस्पद बयान दे रहे हैं, यह जानते हुए कि यह उनकी पद की शपथ का उल्लंघन है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एडिटर्स गिल्ड के पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से पुनः राहत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 15 सितम्बर। सर्वोच्च न्यायालय ने "एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया" (ई.जी.आई.) के चार सदस्यों

- सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें किसी भी दंडात्मक कार्यवाही से दो सप्ताह की सुरक्षा और प्रदान की। ज्ञातव्य है कि, 4 सितम्बर को मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एडिटर्स गिल्ड के चार पत्रकारों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई थी।

को अबपीडक कार्यवाही (कोअर्सिव एक्शन) में संरक्षण की अवधि को शुक्रवार को दो सप्ताह और बढ़ा दिया है। ज्ञातव्य है कि इन चार पत्रकारों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)